कोयला धोवनशालाओं का निजीकरण

1472 श्रीमती सुषमा स्वराज:
श्री कृष्ण कुमार बिरला:

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने कोयला खानों में धोवनशालाओं की स्थापना के लिए निजी क्षेत्र को रियायतें देने का निर्णय किया है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंत में कोयला साफ करने की कुल स्थापित क्षमता कितनी थी;

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कोयला साफ करने की कुल स्थापित-क्षमता का औसतन कितना प्रतिशत प्रतिवर्ष उपयोग में लाया गया;

(घ) कोयला धोवनशालाओं द्वारा इस समय कोयले की कितनी मात्रा को साफ किया जा रहा है और उनके कार्य करने के ढंग को अधिक संगत बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार ने वर्ष 1992-93 के दौरान देश में उत्तम किस्म के की मांग का मूल्यांकन किया था;

(च) यदि हां, तो वर्ष 1992-93 के दौरान इसकी आवश्यकता कितनी थी और वर्ष 1996-97 के दौरान अनुमानत: इसकी मांग कितनी होगी; और

(छ) सरकार ने देश में वर्ष 1996-97 तक कितने कोयले को साफ करने की क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) जी, हां। निजी क्षेत्र में कोयला वाशरियां स्थापित किए जाने के लिए कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 का संशोधन संसद द्वारा पारित कर दिया गया है तथा इसका अधिनियम किया जाना है।

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति पर देश में कोयले की धुलाई के लिए कुल प्रतिष्ठापित क्षमता 36.70 मिलियन टन प्रति वर्ष की थी।

(ग) सातवीं योजना अवधि के दौरान कोल इंडिया लि. की वाशरियों की क्षमता उपयोगिता 54.7% से 59.2% के मध्य थी।

(घ) 1992-93 के दौरान कोल इंडिया लि. की वाशरियों ने 17.07 मिलियन टन कच्चे कोयले की धुलाई की। विद्यमान वाशरियों के आधुनिकीकरण का कार्य विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुसार किया जाता है। डिशैलिंग संयंत्र की प्रतिस्थापना, फाइन कोल परिष्करण का प्रावधान कच्चे कोयले की फाइनर ग्रेडिंग की व्यवस्था तथा इंस्ट्रूमेंटेशन आटोमेशन प्रणाली की शुरुआत किया जाना आदि आधुनिकीकरण के कुछ प्रमुख लक्षण हैं, जो कि किए जा रहे हैं।

(ङ) और (च) उच्च ग्रेड वाले अकोककर कोयले तथा धातुकर्मी प्रयोग के-कच्चे कोककर की वर्ष 1992-93 तथा 1996-97 के लिए मांग नीचे दर्शायी गई है :--

(मि. टन)

	1992-93	1996-97
उच्च ग्रेड का अकोककर कोयला	25.50	28.30
कोककर कोयला	31.30	39.00

(छ) कोककर तथा अकोककर कोयला दोनों के लिए उपर्युक्त के संबंध में प्रति वर्ष तकरीबन 29.0 मिलियन टन की अतिरिक्त कोयला वाशरी क्षमता का निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है।

Haphazard mining in Raniganj Coalfields

1473. SHRI BISHAMBHAR NATH PANDE : Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a large number of people are living under constant threat in the Raniganj Coalfield areas due to haphazard mining;

(b) if so, what are the details thereof: and

(c) what measures Government propose to take to ensure safety of the people?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRI AJIT

KUMAR PANJA) : (a) to (c) Some areas in Raniganj Coalfields of West Bengal are prone to subsidence mainly due to unscientific mining carried out in the past before the nationalisation of coal mines. In 1978 a Committee set up by the Government of India had examined all the subsidence prone areas. Government of West Bengal had enacted a legislation called the West Bengal Restriction on Construction in Unsafe Areas Act, 1979 for prevention of construction over the areas declared unsafe. Despite this enactment, constructions have been going on over many unsafe areas.

Some of the steps being taken to deal with the problem of subsidence in Raniganj Coalfield are given below :

(i) Since there is no proven technology for stabilisation of inaccessible water logging workings, an innovative technology of hydro-pneumatic stowing is being given trial in an area near Raniganj township.

(ii) An Apex Monitoring Committee has been constituted by Coal India Limited with representatives of Government of West Bengal, Directorate General of Mines Safety, Central Mine Planning and Design Institute, Eastern Coalfields Limited, local representatives etc., for examination of unsafe areas. The Committee has completed the survey and has declared certain localities in Raniganj Coalfield as unsafe for habitation. Central Mine Planning and Design Institute has taken up formulation of schemes for dealing with each unsafe locality subject to availability of funds.

(iii) Regular follow-up and liaison with the District authorities is maintained for evacuation of people from areas declared unsafe.

Dues of coal companies outstanding against power stations

1474. SHRI SHIV PRATAP MISHRA : Will the Minister of COAL be pleased to state :

(a) whether any dues of coal companies are outstanding against the power stations in the country ;

(b) if so, the total amount due from each power station towards each coal company for the year 1991-92 and so far in 1993 ;

(c) the reasons for which the money could not be recovered so far ; and

(d) what remedial measures have been taken for their recovery ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRI AJIT KUMAR PANJA) : Yes, Sir.

(b) The details of amounts due to Coal India Limited from power utilities as on 1st April, 1992 and 31st March, 1993 were as follows :—

Name of Power Utilities	Data provisional Amount Rs. in crores	
	As on 1-4-1992	As on 31-3-1993
1	2	3
1. Andhra Pradesh Electricity Board	4.45	5.41
2. Ahmedabad Elec. Company	28.99	30.07
3. Badarpur Thermal Power Station . . .	88.90	237.13
4. Bihar State Elec. Board	22.57	27.80